





# 4<sup>th</sup> IP Excellence Awards 2024

Honoring and Celebrating IP change makers of India

8<sup>th</sup> November 2024 | New Delhi



National Council on Intellectual Property Rights
The Associated Chambers of Commerce and Industry of India

India has embarked on a journey towards creating an enabling environment by putting in place an ecosystem that breeds innovation. The Government of India has launched several significant initiatives for propelling innovation, such as the Start-up India initiative, Accelerating Growth of New India's Innovations (AGNIi), Atal Tinkering Labs, new intellectual property rights (IPR) policy etc. All these initiatives, coupled with phenomenal research and innovation from the institutions, industry, and society, are cementing India's position as an innovation and knowledge hub.

ASSOCHAM National Intellectual Property Rights (IPR) Council has been working to promote culture of creativity & innovation in the country and initiated many recognitions over the years like ICT Startups Awards, Intellectual Property Talent Search Examination Awards, IPRISM Awards etc and customised capacity building programmes for Startup, MSMEs, enforcement agencies, technical and non-technical universities, individual innovators, innovation centres etc. We have also established IP facilitation centres to provide handholding services to the innovators in association with the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises (MSME), Government of India with the prime objective to boost Intellectual Property (IP) culture by guiding and assisting in identification, protection and management of Intellectual property Rights (IPRs).

ASSOCHAM under the National Council on Intellectual Property Rights introduced IP Excellence Awards in 2021. Through three successful editions, these prestigious awards have highlighted the invaluable contributions made by IP Changemakers who have revolutionized the Indian IP ecosystem. ASSOCHAM IP Excellence Awards was started with the aim of bestowing recognition and rewards upon exceptional enterprises and enablers within the industry ecosystem. These entities have been instrumental in fostering innovation, creating groundbreaking products, and exhibiting tangible social impact.

The applications for 4th IP Excellence Awards 2024 have been made live from **12th August 2024** and the deadline for submissions is **16 October 2024**.

# CATEGORIES SEGMENT















# **FOCUS SECTORS**

- Engineering/ Manufacturing Sector: Instrumentation, Automobile, Chemicals, Metals and Metallurgy, Textile, Food & Beverages, Machinery, Engines, Electrical and Electronic equipment and other sectors.
- ICT & Services: Software development; Telecommunications activities; Publishing activities, including software publication; motion picture and sound recording activities; radio and TV broadcasting and programming
- Life Sciences: Pharmaceuticals and Biotechnology
- MSMEs: Definition of MSME will be as per the revised Classification applicable w.e.f 1st July 2020. Proof for micro, small and medium enterprises should be submitted either in the form of registration certificate for MSME or certificate by auditor that the company is in MSME category as on December 2021.
- R&D Institutes: Public funded laboratories (under CSIR, DRDO, ISRO, DAE, DST, DBT, MeitY etc.), private sector research labs, autonomous labs set up by Trusts/Societies.
- *IP Facilitators:* IP Firms, IP Service providers, incubation centres and individuals.

# **EVALUATION PROCESS**

ASSOCHAM IP Excellence Awards is a three-stage funnel process:

**Stage 1: Validation of data:** It is done by cross-checking each patent / trademark / design number provided by the applicant with the website of Indian Patent Office and other relevant agencies.

Stage 2: Presentation to Jury: All entries will be presented to jury

**Stage 3: Virtual Interaction:** Experts may seek a physical or virtual interaction with any applicant and ask for information on specific points.

# **NOMINATION FEES**

**Large Enterprises:** Rs. 40,000 + 18% GST

**Small, Medium Micro Enterprises:** Rs. 20,000 + 18% GST

**Legal Firms:** Rs. 20,000 + 18% GST

**R&D Institutes:** Rs. 10,000 + 18% GST

**University/Academic Institutes:** Rs. 10,000 + 18% GST

*IP Service Providers:* Rs. 10,000 + 18% GST

**Incubation Centers:** Rs.10,000 + 18% GST

**Start-ups:** Rs. 2,000 +18% GST



# **Glimpses of Past Editions**





















# Media Coverage

### India granted over 1 lakh patents in FY24: Official

India granted 1.03 lakh patents in financial year 2023-24, Controller General of Patents, Designs and Trademarks Unnat Pandit said on Thursday, as he assured that there will be "no delay" in the Intellectual Property

Office as it prioritises timely clearance of applications. Addressing an Assocham event here, he shared that 40 per cent of the applications were disposed of within 30 months of the request for examination.



### India granted over 1.03 lakh patents in FY24, says official

There will be 'no delay' in the Intellectual Property Office as it prioritises timely clearance of applications'

#### OUR CORRESPONDENT

the enmonite value in IP has design plant filings. Their diseases of the particles of the p



LASE VEB HII beilg grinder in Silver in Silver

"Year over year, the IP filing is increasing, in 2023-24 we get 20,300 potent filing!"
Commerce and includity Ministry had earlier said every 6 minutes one mechaniogy is seeking P protection in India

### • संक्षेप में

### देश में 2023-24 में लाख से अधिक पेटेंट जारी

पेटेंट, डिजाइन और ट्रेडमार्क महानियंत्रक उन्नत पंडित ने गुरुवार को कहा कि देश में वित्त वर्ष 2023-24 में 1.03 लाख पेटेंट जारी किए गए। बौद्रिक संपदा कार्यालय में 'कोर्ड विलंब नहीं' होगा और समय पर पेटेंट आवेदनों का निपटान करना ही पाथमिकता है। उद्योग मंदल एसोचैम के कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुरोध के 30 महीने के भीतर 40 प्रतिशत आवेदनों का निपटारा किया गया। पंडित ने कहा, 'हम आईपी कार्यालय में कोई देरी नहीं करेंगे। यही हमारा उद्देश्य है कि आईपी प्रदान किया जाना चाहिए और अधिनियम के अध्याय-8 के तहत इसका उपयोग आवेदक द्वारा भी किया जाना चाहिए।'

### भारत ने पिछले वित्त वर्ष में एक लाख से अधिक पेटेंट दिए

नई दिल्ली। भारत ने वित्तीय वर्ष 2023-24 में 1.03 लाख पेटेंट दिए। पेटेंट, डिजाइन और टेडमार्क महानियंत्रक उन्नत पंडित ने बहस्पतिवार को यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि जो आवेदन आते हैं उन्हें बौद्धिक संपदा कार्यालय (आईपीओ) में बिना देरी के समय पर मंज़री दी जाती है।

 एक औद्योगिक संगठन के कार्यक्रम में उन्होंने कहा, भारत को अपनी बौद्धिक संपदा स्थिति को मजबूत करने की जरूरत है। साल दर साल बौद्धिक संपदा (आईपी) फाइलिंग बढ रही है। 2023-24 में हमें 90,300 पेटेंट फाइलिंग मिलीं। पेटेंट कार्यालय ने 15 मार्च, 2023 से 14 मार्च, 2024 के बीच प्रत्येक कार्य दिवस पर औसतन 250 पेटेंट प्रदान किए हैं। ब्यूरो

# देश में वित्त वर्ष 2023-24 में एक लाख से अधिक पेटेंट जारी: अधिकारी

डिवाइन तथा ट्रेडमार्क महानियंत्रक उन्तत पंडित ने बृहस्पतिवार को कहा कि देश में वित्त वर्ष 2023-24 में 1.03 लाख पेटेंट जारी किए गए। उन्होंने कहा कि बौदिक संपदा (आईपी) कार्यालय में कोई संपदा स्थित को मजबूत करने की विलंब नहीं होगा और समय पर पेटेंट आबेदनों का निपटान करना ही प्राथमिकता है। उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुरोध के 30 महीने के भीतर 40 प्रतिशत आवेदनों का निपेटारा किया गया। पंडित ने कहा, हम आईपी कार्यालय में कोई देरी नहीं करेंगे... यही हमारा उद्देश्य है कि..आईपी प्रदान किया जाना चाहिए और अधिनियम के अध्याय-८ के तहत इसका उपयोग आबेदक द्वारा भी किया जाना चाहिए ...। उन्होंने कहा, सभी लंबित आवेदन का निपटान हो गया प्राप्त हुए।

नई दिल्ली, (भाषा)। पेटेंट, है इसलिए अब जो भी आवेदन जांच या सुनवाई के लिए आएंगे..उनका निपटान 30-36 महीने में किया जाएगा। इसलिए अब कोई विलंब नहीं होगा। पंडित ने भारत के अपनी बौद्धिक जरूरत की भी बात कही।उन्होंने कहा, हर साल पेटेंट के लिए आबेदन बढ़ रहे हैं। 2023-24 में हमें 90,300 पेटेंट के लिए आवेदन मिले। न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में बल्कि सुरक्षा पर भी पर्याप्त जोर है। पेटेंट के लिए आवेदन की उच्च संख्या शोध के क्षेत्र में भरोसे की बताता वाणिज्य और उद्योग €...1 मंत्रालय ने पहले कहा था कि देश में हर छह मिनट में एक प्रौद्योगिकी बौद्धिक संपदा सुरक्षा की मांग कर रही है। 2023 में, अब तक के उच्चतम 90,300 पेटेंट आवेदन

टेश में वित्त वर्ष 2023-24 में एक लाख से अधिक पेटेंट जारी
माई दिल्ली। पेटेंट हिजाहन तथा
देखाई मांगिरनेक उनता
परित ने सुम्परीत्राम के कार्ता
के देश में बिता कर 2023-24 में
1,03 एडवा पेटेंट आदी किया गांव रहते में साम के देश में किया मांगिरने कहा कि बीदिक मंदव (आईगे), कार्तालय में 'कोर्ट क्या कार्यालय में 'कोर्ट क्या किया की मांगा और स्थाप पर ब ग्रीड क्या के स्थाप के मांगिरन के कार्यालय में कोर्ट विश्व मांगिरन में क्या के स्थाप मांगिरन में कार्यालय में मांगिरन में क्या मांगिरन में क्या मांगिरन मांगिरन के मांगिरन भी कर्ता हुए अमीर कहा कि मार्ग्यों में के प्रवास की प्रामानक आवेदनों के निपटस्था किया ग्या।
पीडित में कहा, 'हम्म आईमें अधिक पेटेंट जारी

असेटरी का निपटाय किका क्या । पिडार में कहा, 'कम कांधी पिडार में कहा, 'कम कांधी प्रधान किया आहें हैं के आहेंगे, बसी समया उदेशन हैं कि आहेंगे, प्रधान किया आहेंगा कांधिए कीं अधिनियम के अप्रधान के की आहें किया के अप्रधान के कांधी प्रविद्या में किया जमा आहेंगा अखेंदर का निपटान के मान है असीटर अब जो भी आवेंदर कांधी अस्ति कांधी में अस्ति कांधी में अस्ति कांधी आहें में किया जागा। उसीटर अध्ये अहें अबें कोंधी किया जागा। उसीटर अध्ये अहें अब कोंधी कांधा उसीटर अध्ये आहें

# देश में एक साल में जारी हुए एक लाख से अधिक पेटेंट : अधिकारी

जनसत्ता ब्यूरो नई दिल्ली, 25 अप्रैल।

पेटेंट, डिजाइन तथा ट्रेडमार्क महानियंत्रक उन्तत पंडित ने गुरुवार को कहा कि देश में विन वर्ष (2023-24) में 1.03 लाख पेटेंट जारी किए गए हैं। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपदा (आईपी) कार्यालय में 'कोई विलंब नहीं' होगा और सभी पेटेंट संबंधी आवेदनों का समय पर निपटान करना ही प्राथमिकता है।

उद्योग मंडल एसोचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि पेटेंट के लिए अनुरोध के 30 महीने के भीतर 40 फीसद आवेदनीं का निपटारा किया गया। पंडित ने कहा कि बीटिक संपदा कार्यालय में कोई देरी नहीं करेंगे। हमारा उद्देश्य है कि बौद्धिक संपदा प्रदान करने के लिए अधिनियम के अध्याय-s के तहत इसका

उपयोग आवेदक द्वारा भी किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि सभी लेंबित आयेदन का निपटान हो गया है इसलिए अब जो भी आयेदन जांच या सुनवाई के लिए आएंगे उनका निषटान 30-36 महीने में किया बाएगा। उन्होंने आस्वस्त किया कि अब देरी नहीं होगी। पंडित ने भारत के अपनी बौद्धिक संपदा स्थित को मजबूत करने की आवस्थकता बताते हुए कहा कि हर साल पेटेंट के लिए आवेदन बढ़ रहे हैं। 2023-24 में पेटेंट के लिए 90,300 आवेदन मिले, निसमें ना केवल थिजान और प्रौद्योगिकी बल्कि सुरक्षा क्षेत्र पर भी पर्याप्त जोर है। पेटेंट के लिए आवेदन की उच्च संख्या शोध के क्षेत्र में बढ़ते कारम और भरोसे को बताता है। व्यक्तिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पहले कहा था कि देश में हर छह मिनट में एक प्रौद्योगिकी वीदिक संपदा सुरक्षा की मांग कर रही है।

2023 में अब तक के उच्चतम 90,300 पेटेंट आवेदन प्राप्त हुए।

# 2023-24 में एक लाख से अधिक पेटेंट जारी

डिजाइन तथा ट्रेडमार्क महानियंत्रक उन्नत पंडित ने गुरुवार को कहा कि देश में वित्त वर्ष 2023-24 में 1.03 लाख पेटेंट जारी किए गए। उन्होंने कहा कि बौद्धिक संपद्म (आईपी) कार्यालय में' कोई विलंब नहीं' होगा और समय पर पेटेंट आवेदनों का निपटान करना ही प्राथमिकता है।

ापदान करना ही प्राथानकता ह। उद्योग मंडल एसाँचैम के एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि अनुरोध के 30 महीने के धीतर 40 प्रतिशत आवेदनों का निपदारा किया गया। पेंडिंत ने कहा कि हम आईपी कार्यालय में कोई देरी

30 महीने के भीतर 40 पतिशत आवेदनों का निपटारा किया गया

नहीं करेंगे... यही हमारा उद्देश्य है कि...आईपी प्रदान किया जाना चाहिए और अधिनियम के अध्याय-8 के तहत इसका उपयोग आवेदक द्वारा भी किया जाना चाहिए । उन्होंने कहा कि सभी लंबित आवेदन का निपटान हो सथा है इसलिए अब जो भी आबंदन जांच या सुनवाई के लिए आएंगे, उनका निपटान 30-36 महीने में किया जाएगा। इसलिए अब

कोई विलंब नहीं होगा। पंडित ने भारत के अपनी बौद्धिक संपदा स्थिति को मजबत करने की जरूरत की भी बात कक्षा उन्होंने कहा कि है साथ उट्ट के लिए आवेदन बढ़ रहे हैं 12023-24 में हमें 90,300 पेटेंट के लिए आवेदन मिले। न केवल विज्ञान और प्रौद्योगिकों के क्षेत्र में बल्कि सुरक्षा पर भी पर्याप्त जोर है। पेटेंट के लिए आवेदन की उच्च संख्या शोध के क्षेत्र में भरोसे की बताता है। वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय ने पहले कहा था कि देश में हर छह मिनट में एक प्रौद्योगिकी बौद्धिक संपदा सुरक्षा की

### Partners and Winners IP excellence Awards 2022 and 2023

























































































### For more information, please contact: